पटना के उच्च न्यायालय में (विशेष पीठ)

1958 के सिविल संदर्भ संख्या 1

निर्णय हुआः 09.01.1961

याचिकाकर्तागणः **के संदर्भ मेंः रामेश्वर प्रसाद सिन्हा**

कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879-धारा 13 (बी),14-अदालत में इजराय वाद में जमा किए गए आवेदक से संबंधित-बिक्री आय को अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद सिन्हा ने अपने क्लर्क गिरिजा प्रसाद के साथ मिलीभगत में वापस ले लिया। (पैरा-1)

अधिवक्ता के रूप में कर्तव्य का निर्वहन सावधानी और परिश्रम का प्रयोग करने में विफल रहा-अधिवक्ता ने न तो संतुष्ट करने की जहमत उठाई और न ही अपने लिपिक से मुवक्किल को वास्तविक भुगतान के बारे में कोई पूछताछ की, जिस क्लर्क ने पैसे निकले वह भी मुवक्किल का निजी कार्पिरडाज़ भी था, अधिवक्ता पृष्ठांकन के बाद भुगतान के बारे में जांच करना आवश्यक नहीं समझा-वास्तविक भुगतान के बारे में पुष्टि करने के लिए मुवक्किल की ओर से भुगतान आदेश प्राप्त करने वाले अधिवक्ता और मामले को पूरी तरह से लिपिक के हाथों में नहीं छोड़ दिया-न कि घोर लापरवाही या पेशेवर कदाचार का मामला बनता है। (पैरा-3)

पटना के उच्च न्यायालय में (विशेष पीठ)

1958 के सिविल संदर्भ संख्या 1

निर्णय हुआः 09.01.1961

याचिकाकर्तागणः **के संदर्भ मेंः रामेश्वर प्रसाद सिन्हा**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

खलील अहमद, एस.सी. मिश्रा और उदय सिन्हा, न्यायमूर्तिगण

सलाहः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः सरकारी अधिवक्ता और अधिवक्ता, लाला राजेंद्र प्रसाद

प्रत्यर्थियों/प्रतिवादी के लिए अधिवक्ताः जे.सी. सिन्हा, अधिवक्ता।

आदेश

1. जिला न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा दिनांक 7 मई, 1958 को प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर, इस पीठ द्वारा 1 अगस्त, 1958 को एक नियम जारी किया गया था, जिसमें श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, याचिकाकर्ता, मुंगेर से कारण बताने के लिए कहा गया था कि उनके खिलाफ कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 13 (बी) और 14 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, अब उपस्थित हुए हैं, और हमने श्री जे. सी. सिन्हा को सुना है, जो श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा की ओर से पेश होते हैं। श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि रु. 800-14-6, अपीलकर्ता बाबू लाल साओ से संबंधित अतिरिक्त बिक्री आय होने के कारण 1953 के निष्पादन मामले संख्या 65 में मुन्सिफ द्वितीय न्यायालय, मुंगेर की अदालत में जमा किया गया था और आवेदक ने 16 नवंबर, 1956 को श्री चतुरानंद मिश्रा, वकील के माध्यम से राशि की निकासी के लिए एक याचिका दायर की थी। भुगतान आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि

वापस लेने के लिए मांगी गई राशि के लिए एक भुगतान आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था। अभिलेख के सत्यापन पर, बाद में यह प्रतीत हुआ कि श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, ने गिरजा प्रसाद के साथ मिलकर पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मोंघिर से पैसे निकाल लिए थे, इसके बाद श्री आर. पी. टंडन, मुन्सिफ द्वारा बाबू लाल साओ द्वारा दायर आवेदन पर जांच की गई। श्री टंडन ने पक्षों को सुनने के बाद कहाः

> "नतीजतन, मैं इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, विरोधी पक्ष संख्या 1 के खिलाफ मुवक्किल के पैसे को बनाए रखने और दुरुपयोग करने जैसे पेशेवर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है और इसलिए, अभिलेख को कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवश्यक आदेशों के लिए माननीय उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जा रहा है। "

यह आदेश 30 अगस्त, 1957 का है। इसके बाद जिला न्यायाधीश ने 7 मई, 1958 के अपने आदेश द्वारा मामले का पूरा अभिलेख आवश्यक कार्रवाई के लिए इस अदालत को भेज दिया, जिसके बाद इस अदालत द्वारा पहले से ही उल्लिखित नियम जारी किया गया था।

2. श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा ने मुन्सिफ के समक्ष अपनी याचिका में स्वीकार किया था कि उन्हें भुगतान आदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद अपने लिपिक गिरिजा प्रसाद के नाम पर इसका समर्थन करते हुए उन्हें यह निर्देश देते हुए सौंप दिया कि उन्हे बाबू लाल साओ को भुगतान करना चाहिए, इसलिए, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए धन को किसी भी तरह से उनके द्वारा रोक लिया गया था। फिर गिरिजा प्रसाद द्वारा दायर कारण बताओ याचिका से पता चलता है कि उन्होंने उक्त बैंक से पैसे निकाले और उसके बाद बाबू लाल साव से इसकी रसीद मिलने पर उसी का भुगतान किया।

वह रसीद 12 जून, 1956 की है। इसके बाद, हालांकि, जब मामला अभी भी जिला न्यायाधीश की अदालत में लंबित था, कहा जाता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता बाबू लाल साओ को एक और भुगतान किया था, और इस भुगतान के समर्थन में बाबू लाल साओ द्वारा एक और रसीद जारी की गई थी। यह रसीद 21 सितंबर 1957 की तारीख की है।

3. हमने अभिलेख पर मौजूद सभी सामग्रियों को ध्यान से देखा है, और श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा के खिलाफ हमारे सामने जिस मुख्य बात पर जोर दिया गया है, वह यह है कि एक वकील के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वह उस सावधानी और परिश्रम का प्रयोग करने में विफल रहे जो उन्हें करना चाहिए था-जितना कि उन्होंने एक बार अपने लिपिक के पक्ष में भुगतान आदेश का समर्थन किया था, उसके बाद कभी भी खुद को संतुष्ट करने की जहमत नहीं उठाई कि उस भुगतान आदेश के आधार पर बैंक से निकाले गए धन का वास्तव में कभी भी बाबू लाल साव को भुगतान किया गया था। अब इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने वास्तविक भुगतान के बारे में कभी कोई पूछताछ नहीं की।

लेकिन हमारी राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर केवल उनकी ओर से यह उदासीनता निर्णायक रूप से उनके खिलाफ घोर लापरवाही या पेशेवर कदाचार का मामला नहीं है; क्योंकि, आखिरकार, यह पक्षों का स्वीकार किया गया मामला है कि गिरजा प्रसाद जिन्होंने वास्तव में बैंक से पैसे निकाले थे, न केवल वकील के लिपिक थे, बल्कि बाबू लाल साव के निजी कारपरडाज़ भी थे। इस कारण से, इसलिए, यह काफी समझ में आता है कि विद्वान वकील ने, एक बार समर्थन करने के बाद, वास्तविक भुगतान के बारे में उसके बाद कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा होगा।

हालाँकि, हम एक ही समय में यह आंकलन करने में मदद नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के मामले में एक नियम के रूप में यह हमेशा सुरक्षित और वांछनीय है कि एक वकील को अपने मुवक्किल की ओर से भुगतान आदेश प्राप्त करते समय यह देखने योग्य बात होना

चाहिए कि वही या बैंक से उसके बदले में प्राप्त धन वास्तव में संबंधित व्यक्ति को भुगतान किया जाता है और मामले को पूरी तरह से उसके लिपिक के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा उस पर रखे गए विश्वास का किसी न किसी रूप में दुरुपयोग किया जाने का खतरा बना रह सकता है। इसलिए, हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस संबंध में एक बेहतर तरीके और आचरण का पालन किया जाएगा।

4. उपरोक्त अवलोकन के साथ, इसलिए, नियम का निर्वहन किया जाता है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में, लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।